

विनियमन के उभरते पहलू*

श्री संजय मल्होत्रा

मुझे एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में आप सभी के बीच आकर प्रसन्नता हो रही है। देश के बैंकिंग और वित्त जगत के नेताओं को संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं एसबीआई के अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब हम निरंतर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक पुनर्गठन और तेजी से तकनीकी परिवर्तन की दुनिया में कार्य कर रहे हैं। यह न केवल कई चुनौतियाँ लेकर आता है बल्कि कई अवसर भी लाता है।

मुझे याद है कि लगभग एक वर्ष पहले, जब मैंने राजस्व सचिव के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित किया था, तो मैंने कर सुधारों के बारे में बात की थी। आज अपने संबोधन में, मैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए विनियामकीय उपायों पर ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे पहले, हमने विनियमन की रूपरेखा जारी की थी। हम एक परामर्शी प्रक्रिया का पालन करते हैं, प्रभाव विश्लेषण करते हैं और नियमों के उद्देश्य तय करते हैं। इस ढांचे की भावना में, मैं प्रमुख नियमों के उद्देश्यों और औचित्य पर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ।

“विनियमन” का उद्देश्य

इस संदर्भ में, मैं उस बात को भी दोहराना चाहूंगा जो मैंने इस साल फरवरी में अपने पहले एमपीसी वक्तव्य में कहा था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हित वित्तीय स्थिरता की मांग करता है। रिज़र्व बैंक में हमारे लिए, वित्तीय स्थिरता लक्ष्य बना हुआ है, क्योंकि वित्तीय स्थिरता की कीमत पर हासिल की गई अल्पकालिक वृद्धि दीर्घकालिक विकास के लिए बड़े परिणाम हो सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि वित्तीय अस्थिरता न केवल उच्च अल्पकालिक संवृद्धि के लाभ की भरपाई से अधिक हो सकती है, बल्कि वसूली को अधिक कष्टप्रद और लंबा बना सकती है।

साथ ही, आर्थिक हित के लिए दक्षता बढ़ाने और नवोन्मेष

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा द्वारा 12वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव, मुंबई, 07 नवंबर 2025 को दिया गया मुख्य भाषण।

को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो भी हमारा कर्तव्य है। हम मानते हैं कि जिस तरह कुछ भी मुफ्त नहीं है, उसी तरह स्थिरता बढ़ाने के लिए विनियमन भी बिना कीमत की नहीं है। यह स्थिरता और दक्षता के बीच ट्रेड-ऑफ है।

मैंने आश्वासन दिया था कि हम विनियम बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। मैंने उल्लेख किया था कि प्रत्येक विनियमन के लाभों और लागत को ध्यान में रखते हुए सही संतुलन बनाने का हमारा प्रयास होगा। हाल के विनियामक प्रस्ताव इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं - नवोन्मेष और विकास की गति और संरक्षा के बीच संतुलन।

इसके अलावा, तेजी से विकसित हो रही बैंकिंग प्रणाली में, विवर्तनिक परिमाण की तकनीकी प्रगति के आधार पर, कोई भी विनियामक एक समय पर प्रणाली को स्थापित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। विनियामक की भूमिका रेलिंग के भीतर इसके विकास का मार्गदर्शन करना है जो स्थिरता, निष्पक्षता और लचीलापन सुनिश्चित करता है।

भारत में, इस दर्शन ने विनियमन के प्रति आरबीआई के दृष्टिकोण में स्थिर अभिव्यक्ति पाई है, जिसे उत्तरदायी रुढ़िवादिता कहा जा सकता है - एक मॉडल जो स्थिरता को महत्व देता है लेकिन सुधार के लिए खुला रहता है।

भूमिका

इस संदर्भ में, भारतीय वित्तीय प्रणाली में पिछले दशक के दौरान हुए घटनाक्रमों को संक्षेप में दोहराना प्रासंगिक होगा।

जीएफसी के बाद, आक्रामक राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन को देखते हुए, विनियामकी छूट से “ट्विन बैलेंस शीट» समस्याएँ उत्पन्न हुईं - अति-उधार वाले कॉर्पोरेट्स और दबावग्रस्त बैंक बैलेंस शीट। बाहरी क्षेत्र की कमजोरियों की अभिव्यक्ति के साथ, भारत को तथाकथित «फ्रैजाइल फाइव» में शामिल किया गया।

“कभी भी अच्छे संकट को बर्बाद न करें” के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, 2014 की अवधि ने वित्तीय प्रणाली के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए एक मूलभूत सर्जरी की ओर अग्रसर किया।

यह बैंकिंग प्रणाली की मान्यता, समाधान और पुनर्पूजीकरण के उद्देश्य से विनियामक उपायों की एक शृंखला द्वारा संचालित किया गया था। 2015 में शुरू किए गए एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) ने बैंकों को अपने ऋण बही की वास्तविक स्थिति को पहचानने के लिए बाध्य किया, जिससे छिपे हुए एनपीए बैलेंस शीट पर आ गए। पर्यवेक्षी ढांचे में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए।

साथ ही, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे ने कमजोर बैंकों के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद की। इसके बाद 2020 तक 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 12 में समेकित किया गया। इन उपायों को एक बड़े पुनर्पूजीकरण कार्यक्रम द्वारा अनुपूरित किया गया था, जिसने पूंजी बफर को मजबूत किया और स्वस्थ ऋण को फिर से शुरू करने की उनकी क्षमता को बहाल किया।

2016 में आईबीसी की शुरुआत, और अदालत के बाहर समाधान तंत्र के माध्यम से शुरू किए गए अनुवर्ती समाधान उदाहरणों ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मौलिक रूप से बदल दिया है।

साथ ही, मौद्रिक और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधार किए गए, जिसमें एक लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण व्यवस्था को अपनाना, विदेशी मुद्रा बाजारों को गहरा करना और पूंजी खाते पर क्रमिक उदारीकरण शामिल है।

हाल के दिनों में वित्तीय मध्यस्थता के एक परिष्कृत और स्तरित प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन भी देखा गया है। निंबल फिनटेक और एनबीएफसी अब सोर्सिंग और ओरिजिनेशन में अधिक भूमिका निभाते हैं। पूंजी बाजार का विकास और प्रतिभूतिकरण जैसे क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण चैनल अब जोखिम हस्तांतरण के लिए एक माध्यम प्रदान करते हैं। हाल ही में जारी परियोजना वित्त निर्देश, विनियामकीय अनुमोदन और अवसर की उपलब्धता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करते हैं। प्रस्तावित दूरदर्शी ईसीएल प्रावधान परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट की शीघ्र पहचान में मदद करेगा।

इसके अलावा, भारतीय बैंक आज एक दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के

लिए, क्रेडिट और जमा लगभग 3 गुना¹ तक बढ़ गए हैं। पूंजी बफर भी मजबूत हुआ है- सी.आर.ए.आर. 31 मार्च, 2015 को 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को 17.5 प्रतिशत हो गया है, साथ ही सीईटी-1 इसी अवधि के दौरान 10.43 प्रतिशत से बढ़कर 14.73 प्रतिशत हो गया है। संपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मार्च 2018 में क्रमशः 11.2 प्रतिशत और 5.96 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मार्च 2025 में जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। बैंकों की लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2024-25 के बीच, परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ -0.24 प्रतिशत से बढ़कर 1.37 प्रतिशत हो गया, और इक्विटी पर प्रतिलाभ -2 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। विनियमन इस प्रदर्शन, इन बदली हुई वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

इस विकास का तात्पर्य है कि विवेकपूर्ण नियमपुस्तिकाओं को भी एक कैलिब्रेटेड तरीके से विकसित होना चाहिए क्योंकि बैंक अब मजबूत हैं और पर्यवेक्षण अधिक सतर्क हैं, भले ही वैकल्पिक जोखिम-धारण स्तंभ गहरे हो गए हैं और बाजार-आधारित जोखिम हस्तांतरण तंत्र अधिक प्रभावी हो गए हैं।

हाल के विनियामक उपायों को इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अब मैं कुछ उपायों पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)

मैं सबसे पहले पूंजी बाजार के एक्सपोजर पर मसौदा दिशानिर्देशों के बारे में बात करूंगा। प्रतिभूतियों के बदले व्यक्तियों को ऋण देने की सीमा बढ़ाने और पूंजी बाजार मध्यस्थों को ऋण देने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव समीक्षा की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो 1999 में निर्धारित सीमाओं को रीसेट करने की मांग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से, सीमाओं में संशोधन के साथ एक अधिक संरचित लोन टू वैल्यू (एलटीवी) ढांचा किया गया है, जो अंतर्निहित प्रतिभूतियों के जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।

¹ स्रोत: आरबीआई से संकलित डीबीआईई विवरणी।

बैंक जमा: 2015 – 85.33 लाख करोड़ रुपये; 2025 – 225.8 लाख करोड़ बैंक ऋण: 2015 – 65.36 लाख करोड़ रुपये; 2025 – 182.43 लाख करोड़ रुपये

इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए विनियामकीय सीमाओं को बनाए रखते हुए, ऋण उपकरणों के खिलाफ ऋण पर सीमाओं को हटाने का प्रस्ताव, जोखिम के दृष्टिकोण से दो उपकरणों के बीच मूलभूत अंतर को पहचानता है। ऋण साधन में प्रमुख जोखिम क्रेडिट जोखिम होता है, और ऋण की तरह, क्रेडिट जोखिम को व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के हिस्से के रूप में प्रबंधित किए जाने की उम्मीद है। एक अतिरिक्त सुकून देने वाला कारक यह है कि केवल सूचीबद्ध और निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस युक्तिकरण से बॉण्ड बाजार के विकास के लिए एक अच्छे सकारात्मक फीडबैक लूप को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

जहां तक अधिग्रहण वित्त का संबंध है, इसे एक विकसित वित्तीय प्रणाली के एक अभिन्न तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो वित्तीय संसाधनों के बेहतर आबंटन में मदद करता है। इसकी जरूरत को देखते हुए गैर-बैंक कंपनियों जैसे एनबीएफसी और बॉण्ड मार्केट को पहले से ही इस तरह की फंडिंग प्रदान करने की अनुमति है। बैंकों पर प्रतिबंध हटाने से वास्तविक अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बैंक फंडिंग को डील वैल्यू के 70 प्रतिशत तक सीमित करने, डेट टू इक्विटी रेशियो की सीमा, टियर-1 कैपिटल के सापेक्ष एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट और पात्रता मानदंड जैसे प्रस्तावित उपायों में संकेंद्रण और क्रेडिट जोखिम शामिल होंगे, जिससे बैंकों और उनके हितधारकों को अतिरिक्त व्यवसाय का लाभ उठाने की अनुमति देते हुए सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

बड़े उधारकर्ताओं के लिए बाजार तंत्र

अब मैं निर्दिष्ट उधारकर्ता ढांचे की वापसी की ओर मुड़ता हूँ।

यह ढांचा लगभग एक दशक पहले एक बहुत ही अलग वित्तीय वातावरण में स्थापित किया गया था। यह एक अनूठा उपाय है, जो शायद किसी अन्य देश ने बैंक स्तर पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) को लागू नहीं किया है। उस समय, बैंकिंग प्रणाली दबाव के ऊंचे स्तर से जूझ रही थी, जो अब ऐसा नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की टियर 1 पूंजी 2016 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से 3.2 गुना बढ़कर पिछले दस वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

दूसरी ओर, तब से कॉर्पोरेट्स के लिए बैंकों के एक्सपोजर का कुल हिस्सा काफी कम हो गया है। विनियामक परिदृश्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। बड़ा एक्सपोजर फ्रेमवर्क, जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है, अब अच्छी तरह से स्थापित है और पर्यवेक्षी टूल किट में काफी सुधार हुआ है। इसलिए, बैंकों द्वारा बेहतर निगरानी और जोखिम प्रबंधन के साथ मौजूदा ढांचे में व्यापक जोखिम भार और प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

एनबीएफसी के बुनियादी ढांचे के जोखिम के भार में कमी

एनबीएफसी के बुनियादी ढांचे के जोखिम भार के बारे में मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव में जोखिम के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम भार निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, कम जोखिम वाले वजन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा: एक, गुणात्मक मानदंडों का एक सेट है जिसे शुरू से ही पूरा करना होता है, जिसमें जोखिम की अवधि के माध्यम से लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए एक उपयुक्त संविदा भी शामिल है; और दो, एक प्रमुख पुनर्भुगतान मानदंड जो जोखिम भार को कम करने से पहले एक उचित प्रदर्शन ट्रेक रिकॉर्ड प्रदर्शित करेगा।

ईसीबी मानदंडों में संशोधन

जहां तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे का संबंध है, ये उपाय एक मजबूत बाह्य क्षेत्र की पृष्ठभूमि में आते हैं। भारत के चालू खाते में ति4 वित्त वर्ष 25 में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया गया, इसके बाद ति1 वित्त वर्ष 26 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत) का मामूली घाटा दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 690-700 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग 11 महीनों के व्यापारिक आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। पूंजी खाता मजबूत बना हुआ है। अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान विदेशी निवेश (एफडीआई और एफपीआई), विदेशी वाणिज्यिक उधार और एनआरआई जमा के तहत भारत में निवल प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 26.8 बिलियन डॉलर की तुलना में 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक रहा। हमारे अनुमानों से पता

चलता है कि शेष वर्ष के दौरान भी पूंजी प्रवाह काफी मजबूत रहेगा।

ईसीबी ढांचे का पुनर्मूल्यांकन भारत के वित्तीय विकास में एक स्वाभाविक कदम है - जो मजबूत बुनियादी बातों पर आधारित है, विवेक से निर्देशित है, और अपनी शर्तों पर वैश्विक वित्त के साथ जुड़ने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में विश्वास से प्रेरित है।

ऑल-इन-कॉस्ट सीलिंग को हटाने से प्रतिस्पर्धी दरों को प्रोत्साहन मिलेगा और विवेकपूर्ण हेजिंग व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। पात्र ऋणदाताओं के ब्रह्मांड के विस्तार से मूल्य निर्धारण दक्षता में सुधार होगा।

स्वचालित मार्ग के तहत उधारकर्ता की निवल संपत्ति से उधार लेने की सीमा को जोड़ने से ईसीबी उधारकर्ता की ताकत से जुड़ता है, जबकि व्यापार करने में आसानी बढ़ती है। यह सीमा और सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत पर कुल बकाया ईसीबी की समग्र नरम सीमा अत्यधिक बाहरी लीवरेज के जोखिम को कम करेगी।

इसके अलावा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ईसीबी को केवल एफडीआई-अनुपालन वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव है और भूमि या संपत्ति व्यापार जैसी स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट गतिविधि के लिए प्रतिबंधित है।

उपसंहार

उपयुक्त और वृद्धिशील नियम

संक्षेप में, ये सभी उपाय संतुलित और उपयुक्त हैं, जो एक बैंकिंग प्रणाली के आधार पर बनाए गए हैं, जिसे पिछले दशक में व्यवस्थित रूप से मजबूत किया गया है, वित्तीय स्थिरता हमारी नीति संरचना की अटूट आधारशिला बनी हुई है। सभी परिवर्तन प्रकृति में वृद्धिशील हैं। हम बुद्धिमानी से और धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं; जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं, वे ठोकर खाते हैं जो तेजी से दौड़ते हैं।² साथ ही जब हम एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखते हैं, जबकि हम सावधानी से चलते हैं, हमें साहस दिखाने की आवश्यकता होती है। फिर से, मुझे शेक्सपियर की पंक्ति³ की याद आ रही है: *Tis dangerous*

² रोमियो और जूलियट, शेक्सपियर।

³ हेनरी IV, भाग-1।

to take a cold, to sleep, to drink; but ... out of this nettle, danger, we pluck this flower, safety. इसलिए, ये उपाय नई सोच को दर्शाते हैं, लेकिन वृद्धिशील हैं और कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते हैं।

समग्र रूप से विनियमन

इसके अलावा, किसी भी विनियामक उपाय को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता है। प्रत्येक उपाय को विनियामक विकास की निरंतरता में देखा जाना चाहिए, न कि अलगाव में। इन प्रस्तावों को व्यापक विनियामक पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए, जो जोखिमों को कम करता है। साथ में, नियम प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रण में रखने के लिए एक बहुस्तरीय रक्षा बनाते हैं। पूर्ण विनियामक परिदृश्य को समझे बिना केवल एक विनियमन का विश्लेषण करने से पेड़ों के लिए जंगल गायब होने जैसा जोखिम होता है।

अनुभव के आधार पर संशोधन

मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बैंकों पर रखी गई उच्च जिम्मेदारियां उनके पिछले प्रदर्शन पर आधारित होती हैं। यह पिछले दशक में बैंकों द्वारा बेहतर शासन और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण है। जैसा कि पहले बताया गया है, पूंजी बफर मजबूत होते हैं, लाभप्रदता बेहतर होती है, और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। समय की वास्तविकताओं और बैंकों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए विनियमन विकसित करना होगा।

सीखने और खोज करने को बढ़ावा देना

इसके अलावा, कोई भी विनियामक बोर्डरूम निर्णय का विकल्प नहीं कर सकता है, या करना चाहिए, खासकर हमारे जैसे विविध देश में। प्रत्येक मामला, प्रत्येक ऋण, प्रत्येक जमा, प्रत्येक लेनदेन अलग-अलग जोखिमों और अवसरों के साथ अलग-अलग होता है। हमें विनियमित संस्थाओं को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि सभी नियमों के लिए एक आकार निर्धारित किया जाए। यह विनियमित संस्थाओं को प्रयोग करने और नवोन्मेष करने, सीखने और सुधार करने में सक्षम करेगा।

सीमाओं के साथ विनियम

साथ ही, जहां कहीं भी हम अब तक निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं या प्रतिबंधों को कम कर रहे हैं, हमने सुरक्षा

और विवेक सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है।

विनियमन और पर्यवेक्षण साथ-साथ चलते हैं।

मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूँ कि एक विनियामक की भूमिका एक माली की तरह होती है जिसका काम पौधों के विकास के लिए «सक्षम वातावरण» प्रदान करने के साथ नहीं रुकता है। माली पौधे के विकास की निगरानी करता रहता है और एक सामूहिक व्यवस्थित सुंदर बगीचे को आकार देने के लिए अवांछित विकास की छंटाई करता रहता है। आरबीआई के पास उभरते जोखिमों को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं - जोखिम भार, प्रावधान मानदंड और प्रतिचक्रीय बफर। इतिहास कार्य करने के लिए हमारी तत्परता को दर्शाता है, जैसा कि हाल ही में नवंबर 2023 में उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार बढ़ाने के मैक्रोप्रूडेंशियल उपायों में देखा गया है। कहने की जरूरत नहीं है, पर्यवेक्षी कार्रवाइयों ने हमेशा अवांछित विकास को कम करने और एक मजबूत और लचीली बैंकिंग प्रणाली को आकार देने के लिए प्रभावी बैकस्टॉप को सक्षम बनाया है।

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इनमें से अधिकांश उपाय औपचारिक परामर्श के लिए जारी किए गए मसौदे के रूप में हैं। ये विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन के साथ बड़े विचार-विमर्श, अनौपचारिक परामर्श और विचार के बाद जारी किए गए हैं, और हालांकि वे व्यापक दिशा को दर्शाते हैं, लेकिन वे अंतिम नहीं हैं। हम सभी हितधारकों से इनपुट लेने के बाद उन्हें अंतिम रूप देंगे।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में शुरू किए गए परिवर्तनों पर भी बात करना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ाने और शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है।

इस दिशा में, बड़े आरई में आंतरिक लोकपाल ढांचे में सुधार करने का प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक लोकपाल योजना को भी इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाया जा रहा है।

विनियामकीय के प्रयासों को बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि विनियमित संस्थाएं निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर और अनुचित लागत के बिना तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करें। विनियमित संस्थाएं समय-समय पर और नियमित विषयगत अध्ययनों के माध्यम से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन कर सकती हैं। इसके अलावा, प्रणालीगत मुद्दों, प्रक्रियाओं में कमी और दोहराए जाने वाली शिकायतों और उपचारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए शिकायतों का प्रभावी मूल कारण विश्लेषण भी किया जा सकता है।

मैं यहां उपस्थित एमडी, सीईओ और अन्य शीर्ष अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना पूर्ण समर्थन दें और यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें कि प्रस्तावित परिवर्तन, जब उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है, तो न केवल अक्षरशः बल्कि भावना में भी लागू किया जाता है।

निष्कर्ष

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण कैलिब्रेटेड है: बैंकों को संवृद्धि, नवोन्मेष और व्यापार करने में आसानी के लिए अधिक वाणिज्यिक छूट प्रदान करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि जोखिम कम से कम हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

हमने 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें वित्तीय क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। आरबीआई इस लक्ष्य के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी वित्तीय प्रणाली नवोन्मेष, संवृद्धि और दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता में सहयोग करे।

मुझे विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव में होने वाले विचार-विमर्श से संवृद्धि के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं इस पहल के लिए एसबीआई की सराहना करता हूँ और कॉन्क्लेव की बड़ी सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद। जय हिंद।